भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *313

गुरुवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक)

रोजगार सृजन कार्यक्रम

***313 श्री रायगा कृष्णैया:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रोजगार सृजन योजनाओं की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन योजनाओं से वास्तव में देश में बेरोजगारी कम हुई है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ड) क्या सरकार मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करना चाहती है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में श्री रायगा कृष्णैया, सांसद द्वारा दिनांक 21.08.2025 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *313 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (च): रोज़गार सृजन के साथ-साथ रोज़गार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोज़गार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के अलावा, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया योजना, आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण यहां https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रोजगार सृजन की योजनाओं की प्रगति का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

पिछले तीन वर्षों के लिए इन योजनाओं का बजटीय आवंटन और व्यय https://www.indiabudget.gov.in/budget2023-24/doc/eb/allsbe.pdf,https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25/doc/eb/allsbe.pdf और https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/allsbe.pdf पर उपलब्ध है। इसके अलावा, बजटीय आवंटन और व्यय योजना के प्रावधान के अनुसार हैं।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 से 2023-24 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

(% में)

वर्ष	**यूआर**	**डब्ल्यूपीआर**
2021-22	4.1	52.9
2022-23	3.2	56.0
2023-24	3.2	58.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि देश में वर्ष भर में रोजगार को दर्शाने वाले अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में वृद्धि की प्रवृत्ति है तथा बेरोजगारी दर में कमी की प्रवृत्ति है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ने 2014 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) को लागू किया और यह 30 सितंबर, 2024 को समाप्त हो गया। मिशन का उद्देश्य लाभकारी स्वरोजगार और कुशल वैतनिक रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के माध्यम से शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा की भावना को कम करना है, ताकि शहरी गरीबों के लिए मजबूत मौलिक संस्थानों के निर्माण के माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सुधार हो सके।

*****

अनुबंध- I

राज्य सभा के दिनांक 21.08.2025 के तारांकित प्रश्न *313 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत रोजगार सृजन हेतु योजनाओं की प्रगति का राज्यवार विवरण

क्रसं..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	पीएमईजीपी	एमजीएनआरईजीए	डीडीयू-जीकेवाई	आरएसईटीआई	पीएम स्वनिधि योजना	पीएमएमवाई	डीए-एनयूएलएम	
		अनुमानित रोजगार सृजन	सृजित मानव दिवस (लाख में)	नियोजित उम्मीदवारों की संख्या	नियोजित उम्मीदवारों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	ऋण खातों की संख्या	नियोजित कौशल उम्मीदवारों की संख्या (30.09.2024 तक)	व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (30.09.2024 तक)
1	अंडमान निकोबार	488	0.88	196	497	6	3,027	0	0
2	आंध्र प्रदेश	25992	2422.82	9033	12038	13588	14,64,680	0	5508
3	अरुणाचल प्रदेश	1248	204.37	265	779	136	36,567	78	0
4	असम	25360	710.78	4127	19080	6136	12,16,262	1361	616
5	बिहार	40280	2502.19	1885	32128	11030	77,71,213	23	761
6	चंडीगढ़	40				48	15,724	44	20
7	छत्तीसगढ	14824	1323.56	1759	14328	10139	10,16,177	0	3403
8	डीएन हवेली और डीडी		2.99		547	63	6,228		
9	दिल्ली	208				13247	1,99,513	0	114
10	गोवा	312	0.76		0	38	27,585	0	1
11	गुजरात*	14264	431.32	2584	22256	27514	15,70,182	325	2599
12	हरियाणा	6304	117.92	3700	15061	14706	8,00,080	15	1682
13	हिमाचल प्रदेश	6368	395.31	2273	7614	116	1,10,348	0	243
14	जम्म कश्मीर	78904	409.38	636	14325	494	3,99,396	0	1090
15	झारखंड	11616	1009.47	4911	19849	4448	16,68,829	207	1034
16	कर्नाटक	22712	1312.38	1914	23696	27483	49,43,477	0	4242
17	केरल	18080	907.54	2572	11355	9413	19,44,890	0	1885
18	लद्दाख	1080	22.19		686	13	12,197	0	1
19	लक्षद्वीप	0	0		419		2,258		
20	मध्य प्रदेश	21008	1897.24	4756	36467	57469	33,02,774	284	4892
21	महाराष्ट्र**	14856	1621.58	4347	30129	57959	44,62,791	1658	3236
22	मणिपुर	4864	244.68	356	2057	70	11,452	0	0
23	मेघालय	8912	320.99	761	2779	746	35,308	156	4
24	मिजोरम	3872	197.75	474	1366	372	26,463	158	39
25	नागालैंड	10096	93.81	570	484	627	32,002	0	20
26	ओडिशा	14936	1193.1	1095	24998	3315	27,93,890	0	2356
27	पुदचेरी	304	10.78	444	880	77	85,730	36	24
28	पंजाब	7760	314.01	3560	13274	10888	7,07,516	648	974
29	राजस्थान	7328	3166.15	4532	32669	31683	21,63,626	0	1486
30	सिक्किम	2528	33.85	393	717	114	19,185	0	0
31	तमिलनाडु	31592	3061.11	4803	29561	15878	45,36,967	0	23318
32	तेलंगाना	14800	1222.87	1271	8149	7647	11,37,388	0	443
33	त्रिपुरा	5840	353.37	694	2765	320	3,48,747	0	153
34	उत्तर प्रदेश।	44144	3364.88	16245	61939	63769	59,24,230	89	4888
35	उत्तराखंड	5872	189.99	2821	9503	2980	3,38,119	0	562
36	पश्चिम बंगाल	10872	0	1969	14864	13579	55,26,827	0	1052
37	कुल	**477664**	**29060.02**	**84946**	**467259**	**406111**	**5,46,61,648**	**5,082**	**66,646**

स्रोत: संबंधित मंत्रालय/विभाग